## 19 जुलाई को खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक

नई दिल्ली, 17 जुलाई। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सबकुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। 19 जुलाई की शाम को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनेवाली है। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में आप और टीएमसी शामिल नहीं होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी सासंद इस बैठक में अपनी रणनीति बनाएंगे।

पिछली इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक लोकसभा चुनाव के बाद 1 जून 2024 को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष

■ सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है।

मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई थी। इसके बाद इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं हुई है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के संसद में फ्लोर लीडर्स की बैठक जून 2025 में हुई थी, जब इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एक साझा खत लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की थी।

सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी नेता 21 जुलाई को होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल नहीं होगी।

# संसद के मानसून सत्र में 8 नए विधेयक लाएगी सरकार

## इसी के साथ 7 लंबित विधेयकों पर भी विचार विमर्श की संभावना है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

■ संसद का मानसून 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 21 बैठकें होंगी क्योंकि 12 से 18 अगस्त तक संसद में अवकाश रहेगा।

नई दिल्ली, 17 जुलाई। संसद का एक माह लंबा मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी, हालांकि 12 अगस्त से 18 अगस्त तक कोई बैठक नहीं होगी। इस सत्र के लिए सात लंबित विधेयकों और आठ नए विधेयकों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

नए विधेयक हैं: जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025, जो व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025; कुछ कर कानूनों में संशोधन हेतु। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, जो खेलों के विकास, खिलाड़ियों के कल्याण और खेलों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025, जो राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अधिनियम, 2022 की परिभाषाओं और प्रावधानों को वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी कोड और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाने तथा राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

इसके अलावा हैं, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति, गहरे खनिजों के लिए खनन पट्टों में सटे क्षेत्रों को शामिल करने, और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के दायरे को विस्तृत करना है। जियोहेरिटेज साइट्स और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2025। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसके तहत आईआईएम गुवाहाटी को भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की अनुसूची में शामिल करना है।

लंबित विधेयकों में शामिल हैं: आयकर विधेयक, 2025; गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024; भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025; व्यापारी पोत विधेयक, 2024; कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024; समुद्र के माध्यम से वस्तुओं का परिवहन विधेयक, 2024; बिल ऑफ लाडिंग विधेयक, 2024।

## 'किस कानून के तहत जज पर मुकदमा हो सकता है?'

नयी दिल्ली,17 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ उनके न्यायिक निर्णयों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सवाल किया कि ऐसा किस कानून के तहत किया जा सकता है। इसके साथ ही,न्यायालय ने इस पर सलाह देने के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई की योग्यता पर सवाल उठाया और याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि किस कानून के तहत

■ सुप्रीम कोर्ट ने जजों के फैसले के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया।

न्यायाधीशों पर निर्णय देने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा, हमें बताइए कि आपके खिलाफ निर्णय देने के लिए न्यायाधीशों पर किस कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि अवैध या विकृत याचिकाएं दायर की जा रही हैं। आप न्यायाधीशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने एक परीक्षा में टॉप किया था, लेकिन विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

# मांगलियावास के पास सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत

## रात दो बजे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर रॉन्ग साइड पर क्षतिग्रस्त हो गई

■ कार में सवार 5 युवक सांवरिया सेठ होते हुए देवमाल्या जोधपुरिया देव के दर्शन के लिए जा रहे थे, जब यह दुर्घटना घटी। चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई तथा पांचवें युवक की हालत चिकित्सालय में गम्भीर बनी हुई है।

अजमेर, 17 जुलाई (कासं)। अजमेर संभाग के ब्यावर जिले में अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में मौके पर चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, मांगलियावास थाना क्षेत्र के लामाना कट के पास रात सवा दो बजे डीडवाना (चौसला गांव) की एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर रॉन्ग साइड में जाकर पलट हो गई। कार में पांच लोग सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

ग्राम पंचायत चौसला के सरपंच प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने बताया कि सभी युवक रात में सांवरिया सेठ होते हुए, देवमाल्या जोधपुरिया देव के दर्शन करने जा रहे थे। मांगलियावास थाना क्षेत्र के लामाना कट के पास रात 2.15 बजे डीडवाना (चौसला गांव) की एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर रॉन्ग साइड में जाकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार चार युवकों में सूरज पुत्र मोहनलाल, बजरंगलाल पुत्र रामलाल, प्रेमचंद पुत्र बोदूराम प्रजापत और कमलेश पुत्र भंवरलाल यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक विमलेश पुत्र कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही मांगलियावास थाने के एएसआई हुकुम सिंह जाप्ते सहित पहुंचे और क्रेन व गैस-कटर की मदद से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार से क्षत-विक्षत शव निकाले।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) गजेन्द्र सिंह भी जेएलएन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मोर्चरी में मौजूद परिजनों से संवेदना जताई और मामले की जानकारी ली। पुलिस द्वारा सूचना मिलने के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आधी-रात को ही परिजन अजमेर के लिए रवाना हो गए। सरपंच प्रतिनिधि शर्मा ने बताया कि वे पुलिस की सूचना पर परिजन के साथ अस्पताल पहुंचे। मृतक चौसला गांव के रहने वाले थे। मृतक प्रेमचंद की पत्नी की एक साल पहले प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। मृतक बजरंग ट्रैक्टर चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

मांगलियावास थाने के एएसआई हुकम सिंह ने बताया कि वे पुलिस दल के साथ रात्रि गश्त पर थे। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि लमाना कट के पास हादसा हुआ है। वे मौके पर पहुंचे। सिंह ने बताया कि हादसा सड़क के विपरीत दिशा में हुआ है, यह पता लगाने का प्रयास कि जा रहा है कि कट के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ या फिर कार तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई। पुलिस ने बताया कि तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

# लगातार बारिश से झालावाड़ के कई इलाके जलमग्न

## पानी की निकासी के लिए भीम सांगर बांध तथा कालीसिंध बांध के गेट खोले

■ गेहूँखेड़ी व अकलेरा के बीच स्थित खाल में जलस्तर बढ़ने से मार्ग अवरूद्ध हो गया। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा। यह इस क्षेत्र की बरसों पुरानी समस्या है जिस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया।

कोटा, 17 जुलाई (निसं)। झालावाड़ जिले में गुरुवार सुबह पौने छह बजे से शुरू हुई बारिश दोपहर तक जारी रही। लगातार बारिश के चलते झालावाड़ के कई इलाके जलमग्न हो गये और कई बांध ओवरफ्लो हो गये और रास्ते भी अवरुद्ध हो गये। ओवरफ्लो के कारण भीमसागर बांध और कालीसिंध बांध के गेट खोले गए। जिले में सुबह आठ बजे तक कुल 279 एमएम बारिश दर्ज की गई।

बारिश के कारण भीमसागर बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। साथ ही, कालीसिंध बांध का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। सुरक्षा की दृष्टि से, भीमसागर डैम का गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी दी गई। प्रशासन ने नागरिकों को नदी के किनारे न जाने की हिदायत दी। जिले के सभी जलाशयों में पानी की आवक जारी है। अकलेरा इलाके में गेहुंखेड़ी और अकलेरा के बीच में स्थित खाल में जलस्तर बढ़ने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। सुबह से ही इस खाल में पानी की आवक हो रही है, पर लोग अपने कामकाज के लिए जान जोखिम में डालकर निकलते रहे। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या बरसों पुरानी है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस समस्या से विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को समय-समय पर अवगत करवाया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को अकलेरा या झालावाड़ जाने के लिए विकल्प के रूप में बारिश के दौरान लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है।

प्रतिदिन बड़ी संख्या में राजकीय कर्मचारी, स्टूडेंट और ग्रामीण अपने कामकाज को लेकर आते- जाते हैं।

## निचली ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

अध्यक्ष नरेन्द्र यादव ने कहा कि गुरुवार को सभी जिला अध्यक्षों की आपात बैठक बुलाई ग, जिसमें तय किया गया कि शुक्रवार से सभी कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अन्य विभागों में कैडर पुनर्गठन कर दिया है, लेकिन हाईकोर्ट की फुल बैंच के निर्णय के बाद भी राज्य सरकार मनमानी कर रही है। गत चार दिनों से प्रदेशाध्यक्ष सहित, अन्य पदाधिकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

इसलिए प्रदेश की समस्त अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इनमें अदालतों के साथ-साथ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य भी शामिल हैं। प्रदेश स्तर पर सामूहिक अवकाश का निर्णय होने का असर प्रदेश की न्यायपालिका पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि राजस्थान की अधीनस्थ न्यायपालिका में करीब 21 हजार से अधिक कर्मचारी हैं।

# 'भारत वहीं से ऑयल खरीदेगा...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम घटनाक्रमों पर बारीक नजर रखे हुए हैं।

प्रस्तावित 'द्वितीयक प्रतिबंध' भारत के उन परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को प्रभावित करेंगे, जो रूसी कच्चे तेल से बनते हैं और जिन पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर सहमत नहीं होते हैं, तो 50 दिनों के अंदर रूसी तेल पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नाटो महासचिव मार्क रुटे ने ट्रंप की बात को दोहराते हुए ब्राज़ील, चीन और भारत को चेतावनी दी कि अगर ये देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो इन पर बहुत कठोर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

भारत रूसी कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक है, जिसकी कीमत प्रति बैरल 60 डॉलर निर्धारित है। यह कीमत वर्तमान अंतरराष्ट्रीय दरों से काफी कम है। भारत रूस से फिलहाल 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात कर रहा है, जो भारतीय कुल तेल आयात का लगभग 42 प्रतिशत है।

रूस से हो रहे कुल आयात का आधे से ज्यादा भारत की तीन रिफाइनरियों द्वारा किया जाता है, जो बाद में परिष्कृत उत्पाद जी 7 देशों को निर्यात करती हैं।

जब अतिरिक्त शुल्क लगेंगे, तो भारत से परिष्कृत उत्पादों का निर्यात बाज़ार में महंगा हो जाएगा। ट्रंप ने रूसी मूल के उत्पादों, जिसमें तेल भी शामिल है, पर लगभग 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी दी है।

भारतीय सूत्र नाटो महासचिव के बयान से हैरान हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ, जिसमें नाटो के घटक देश शामिल हैं, ने 2027 तक रूसी गैस का आयात जारी रखने की योजना बनाई है। एक अधिकारी ने कहा, यह दोहरी बात है तो क्या यूरोप को भी ये अतिरिक्त शुल्क झेलने होंगे?

रुटे ने यह बयान अमेरिकी कांग्रेस में सीनेटरों से मुलाकात के दौरान दिया था। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों की घोषणा की थी, और 50 दिन में कोई शांति समझौता नहीं होने की स्थिति में, रूसी निर्यात के खरीदारों पर 100 प्रतिशत चुभते हुए द्वितीयक शुल्क लगाने की धमकी दी थी।

रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद से भारत रूसी कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार बन गया है और निरन्तर रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाए हुए है। भारत की यह दृढ़ मान्यता है कि जब तक किसी देश पर पर सीधे प्रतिबंध नहीं हैं, तब तक उसे (भारत) यह अधिकार है कि वह वहां से तेल खरीद सकता है, जहां से उसे सबसे अच्छा सौदा मिले।

विशेषज्ञों का कहना है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि नई दिल्ली अमेरिका की धमकियों और उकसावे पर प्रतिक्रिया न देते हुए बेहद सतर्क रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि भारत का यह संतुलित रुख संभवत: ट्रंप को खुश रखने के लिए है, ताकि उसे अमेरिका से बेहतर व्यापार समझौते का लाभ मिल सके।

## 'मुख्यमंत्री के ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

समितियों और पैक्स को सशक्त बना रही है। आज प्रदेश में 41 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। अब तक 976 नए एम-पैक्स का गठन किया जा चुका है। दो वर्षों में शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नया को-ऑपरेटिव कोड लाने की दिशा में कार्य कर रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व की वृहत अन्न भण्डारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों तथा 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण एवं श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी की। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रूपये का ऋण और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण किया। शाह ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से चैक व प्रमाण-पत्र तथा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम से जुड़े जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में 8 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े की सफलता पर आधारित लक्ष्य-पथ-प्रण-अन्त्योदय पुस्तक का विमोचन भी किया। इससे पहले शाह ने 100 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

## अमेरिका की भारत पर ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

में रखकर उठाया जा रहा है, जो रूस के प्रमुख तेल खरीदार हैं और जिनकी वजह से रूसी अर्थव्यवस्था युद्ध जारी रखने लायक बनी हुई है।

ये देश हैं भारत और चीन। ये दोनों रूस से सबसे अधिक तेल खरीदते हैं। अगर उन्हें यह खरीद बंद करनी पड़ी तो उन पर भारी असर पड़ेगा। भारत की कुल तेल जरूरत का 40 प्रतिशत और चीन 20 प्रतिशत रुस से खरीदता है और अचानक बदलाव करना इन दोनों के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है।

लेकिन, अमेरिका के इस कदम से भारत की वैश्विक कूटनीति और आर्थिक स्थिति में एक अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है।

अब बड़े पैमाने पर यह मानी जाने लगी है कि भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था है और उसकी कूटनीतिक ताकत को पहले कम आंका जाता था। अब तक कुछ ही देश मानते थे कि भारत ऐसे वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दों को प्रभावित करने की ताकत रखता है।

लेकिन अब वैश्विक मीडिया में भारत को चीन के बराबर माना जा रहा है, जो रूस पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बना सकते हैं। साथ ही, भारत को एक बड़ा बाज़ार भी माना जा रहा है, जो अमेरिकी कदमों से प्रभावित हो सकता है।

नाटो के महासचिव और नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि वे भारत और चीन से अपील कर रहे हैं कि वे फोन उठाएँ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहें।

लेकिन भारत और चीन दोनों की स्थिति एक जैसी है। दोनों के रूस के साथ लंबे समय से मजबूत राजनयिक संबंध हैं। साथ ही, वे रूसी तेल पर अलग-अलग स्तर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। इतनी जल्दी और बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति के विकल्प तैयार करना बहुत मुश्किल होगा।

## अमरनाथ यात्रा...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

समय, बालटाल मार्ग पर भारी बारिश के चलते अचानक भूस्खलन हो गया। इस हादसे में सोना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के तुरंत बाद उन्हें बालटाल आधार शिविर के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा पर निर्णय लिया जाएगा। बताया जाता है कि अब तक 2.47 लाख तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।

## 'सुपर स्वच्छ लीग शहरों में इंदौर फिर टॉप पर

नयी दिल्ली, 17 जुलाई। इंदौर को लगातार आठवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 'सुपर स्वच्छ लीग शहरों' में इस बार इंदौर को पहला स्थान मिला, जबकि सूरत दूसरे स्थान पर रहा। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 'स्वच्छ शहर' में पहले स्थान पर अहमदाबाद, दूसरे स्थान पर भोपाल और तीसरे स्थान पर लखनऊ रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को यहां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2024-25 में 23 सुपर स्वच्छ लीग शहरों और पंद्रह स्वच्छ शहरों के प्रतिनिधियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। दस लाख जनसंख्या वाले स्वच्छ शहरों में पहला पुरस्कार इंदौर को, जबकि दूसरा, सूरत तीसरा नवी मुंबई को दिया गया।

# 24 घंटे में दूसरी बार उद्धव और फड़नवीस की मुलाकात

## एक के बाद एक हुई दो मुलाकातों से महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का बाज़ार गर्मा गया है

■ गुरुवार को विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कार्यालय में दोनों नेता मिले। इस दौरान आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे।

■ इन मुलाकातों को बुधवार को देवेन्द्र फड़नवीस द्वारा उद्धव को साथ आने के ऑफर से जोड़कर देखा जा रहा है।

पुणे, 17 जुलाई। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद दोनों नेता एक-दूसरे से मिलते नजर आए थे। वहीं, ठीक एक दिन बाद गुरुवार को दोनों नेताओं की मुलाकात विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कार्यालय में हुई। यह बैठक करीब 20 मिनट तक चली। इस बैठक में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। इन दो मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में नई संभावनाओं को जन्म दिया है।

इस मुलाकात पर शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज हमने मुख्यमंत्री को एक संकलन दिया है, जिसमें लिखा है कि पहली कक्षा से तीन-भाषा नीति क्यों नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि बुधवार को विधानसभा में फड़नवीस ने साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2029 तक विपक्ष में जाने वाली नहीं है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को इशारों में संदेश दिया था कि वह चाहें तो किसी अलग रास्ते से सत्तापक्ष में आ सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब उद्धव ठाकरे लगातार गठबंधन सरकार की तीन-भाषा नीति को लेकर आलोचना कर रहे हैं।

शिवसेना और भाजपा ने 25 साल तक साथ मिलकर महाराष्ट्र में राजनीति की। लेकिन 2014 में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में दरार आ गई। 2019 में उद्धव ठाकरे ने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सरकार गिर गई और फडणवीस ने शिंदे के साथ मिलकर सत्ता संभाली।

# हैल्थ इन्श्योरैंस पर लगे जी.एस.टी. में...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

पास स्वास्थ्य बीमा है और टर्म लाइफ बीमा की पहुँच 4 प्रतिशत से भी नीचे है, इतना ऊँचा टैक्स लोगों को बीमा लेने से हतोत्साहित करता है।

रिपोर्टों के अनुसार, जी.एस.टी. काउन्सिल 18 प्रतिशत जी.एस.टी. को घटाकर 5-12 प्रतिशत करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। कुछ विशिष्ट श्रेणियों में पूरी छूट देने की संभावना भी है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इन्श्योरैंस रैग्युरेटरी एण्ड डवलपमैंट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया) और बीमा पर गठित मंत्री समूह ने मिलकर एक साहसिक सुधार की सिफारिश की है: वरिष्ठ नागरिकों के लिए टर्म लाइफ और स्वास्थ्य बीमा पर शून्य जी.एस.टी. दर और 5 लाख तक की पॉलिसियों पर पूरा टैक्स माफ किया जाए।

अगर यह कदम स्वीकृत हो जाता है, तो 2047 तक "हर नागरिक के लिए बीमा" के लक्ष्य की दिशा में यह एक मजबूत कदम होगा। यह नीति निर्माताओं की इस सोच को भी दर्शाता है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यक सुरक्षा उपकरण है, खासतौर पर उस दौर में, जब मेडिकल खर्च और जेब से होने वाले खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं।

बीमा उद्योग के प्रमुख लोगों ने इस संभावित बदलाव का गर्मजोशी से स्वागत किया है। फिनकेडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, मनीष कुमार गोयल ने इस प्रस्ताव को "गेम-चेंजर" बताया। उन्होंने कहा, "जी.एस.टी. को 18 प्रतिशत से घटाकर 5-12 प्रतिशत करना सीधे प्रीमियम की लागत को कम करेगा और बीमा को अधिक लोगों के लिए सुलभ बनाएगा। जब मेडिकल खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसे संरचनात्मक बदलावों की ज़रूरत है, जो नए पॉलिसी खरीदारों को प्रोत्साहित करें।" इंश्योरेंस समाधान की सी.ओ.ओ.शिल्पा अरोड़ा ने भी सहमति जताते हुए कहा, "हेल्थ और टर्म बीमा पर लग्ज़री आइटम जैसा टैक्स नहीं लगना चाहिए। जी.एस.टी. से बीमा महँगा हो जाता है, जबकि पहले ही प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। इसे हटाने या कम करने से बीमा अधिक भारतीयों के लिए एक व्यवहारिक विकल्प बन जाएगा।" बीमापे फिनश्योर के सी.ई.ओ. हनुत मेहता ने इस संभावित नीति बदलाव को "संरचनात्मक सहायक" कहा। उन्होंने कहा, "जी.एस.टी. में कमी न सिर्फ बीमा पॉलिसियों को सस्ता बनाएगी, बल्कि यह हेल्थकेयर फाइनेंसिंग के प्रति भारतीयों के नज़रिए को भी बदल सकती है, जिससे लोग अचानक खर्च करने के बजाय, स्वास्थ्य के लिए पहले से योजना बनाएंगे।

इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। बीमा प्रीमियम पर जी.एस.टी. घटाने से नए और सस्ते प्रोडक्ट लॉन्च करने की राह खुलेगी, जिससे इनोवेशन और बाज़ार में गहरी पैठ बनेगी, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और टियर-2, टियर-3 शहरों में।

ऐसे समय में, जब चिकित्सा खर्च आम परिवारों के बजट पर दबाव डाल रहे हैं और भारत में बीमा लेने की दरें वैश्विक औसत से काफी पीछे हैं, तब जी.एस.टी. काउन्सिल का यह निर्णय एक बदलावकारी (ट्रांसफॉरमेटिव) सुधार साबित हो सकता है। करोड़ों भारतीयों के लिए यह एक सुरक्षित भविष्य की शुरुआत हो सकती है, जिसमें बीमा अब कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि नीति द्वारा समर्थित अधिकार बन जाएगा।

## महेश जोशी...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

की रिश्वत का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, इसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ईडी अपनी रिपोर्ट में जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है। यह राशि कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है। वहीं, इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रहा है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

# राहुल गांधी ने एक बार फिर पूर्व ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

■ पर क्या कुछ लोगों के हाथ, इतनी जिम्मेवारी सौंपना, अक्लमंदी का काम है, राजनीतिक पार्टी के लिए।

गांधी इन दोनों से बहुत प्रभावित हैं।

अब के. राजू को राहुल गांधी के इनर सर्कल और ऑफिस से बाहर कर दिया गया है और वे अब झारखंड ए आई सी सी के प्रभारी हैं, जबकि सैंथिल वर्तमान में पूरी तरह से राहुल के भरोसेमंद और ताक़तवर सहयोगी बने हुए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी, जो आमतौर पर सूक्ष्म मुद्दों में रुचि नहीं लेते, सुबह 10:30 बजे सी ई सी की बैठक में केवल इसीलिए भाग लिया था, ताकि मौजूदा उस समय सांसद जयकुमार का टिकट काटा जा सके और वह टिकट सैंथिल दिया जा सके। राहुल की रुचि केवल उस एक सीट तक सीमित थी। सैंथिल चुनाव जीत गये और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

ऐसा माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों को असीमित अधिकार देने का जो फैसला लिया गया, ताकि कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जा सके, वह सैंथिल के दिमाग की उपज है, और राहुल गांधी ने इस विचार को ऐसे पकड़ लिया है, जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। पूरी पार्टी राहुल गांधी की इस अपरिपक्वता से हतप्रभ है, लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, अर्थात उन्हें रोकने-टोकने की हिम्मत कौन करे।

अब जिला अध्यक्षों की कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। उनके नाम पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तावित किये जा रहे हैं और इससे ज़्यादातर जिलों में भारी गुटबाज़ी शुरू हो गई है, क्योंकि ज़िले के वरिष्ठ नेताओं से कोई सलाह नहीं ली जा रही और अंदरूनी झगड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पी सी सी) अध्यक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, क्योंकि वे हाईकमान द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं। इससे पी सी सी अध्यक्ष और राज्य इकाई की प्रभावशीलता और अधिकार में कमी आयेगी।

जैसा कि एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "इस निर्णय के बाद, कांग्रेस और ज्यादा अराजकता और अव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, क्योंकि नेतृत्व ने इस फैसले के सभी नतीजों और प्रभावों पर सोच विचार नहीं किया है।"

राहुल गांधी के एक और चहेते सहयोगी हैं, कनुनगोलू, जो इस समय बिहार में सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वहां टिकट बांटे जाएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सिफारिशें की थीं, जिन्हें पार्टी ने गंभीरता से लिया था और कांग्रेस दोनों राज्यों में हार गई थी।

राहुल गांधी की मुख्य समस्या यह है कि वे नौकरशाहों और तकनीकी विशेषज्ञों (टैक्नोक्रैट्स) पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, और उनका मानना है कि राजनेताओं पर न तो भरोसा किया जा सकता है और न ही उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेने देना चाहिए।

इस मामले में केवल के. सी. वेणुगोपाल अपवाद हैं, जो कांग्रेस पार्टी में "सारी राजनीतिक समझदारी के संरक्षक" माने जाते हैं।

उन्हें राहुल गांधी ने "पावर ऑफ अटॉर्नी" दे रखी है कि वे सभी अहम फैसले खुद ले सकते हैं।

अब वेणुगोपाल ने जिला अध्यक्षों के संबंध में सभी निर्णयों की ज़िम्मेदारी भी संभाल ली है।

आंध्र प्रदेश के एक नेता चेल्ला वम्शी चंद रेड्डी को जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया देखने और उनके काम-काज व कार्यशैली का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रेड्डी को के सी वेणुगोपाल का नज़दीकी माना जाता है। मनमाने तरीके से निर्णय लेने, राहुल गांधी के करीबी एक छोटे समूह के हाथों में सारी ताकत सिमटने तथा चर्चा एवं बहस के पूर्व अभाव के फलस्वरूप, पार्टी का एक बड़ा हिस्सा पार्टी से दूर हो गया है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908